THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF POWER (SHRI P. V. RANGAYYA NAIDU) : (a) to (c) A Memorandum of Understanding (MOU) has been signed by the Government of Arunachal Pradesh for implementation of Kameng (600 MW) Hydro Electric Project and Kharsang (6 MW) Gas Based Power Project in the private sector, by Intercorp Industries, New Delhi, in collaboration with Snowy Mountains Engineering Corporation of Australia. Clause 8 of the MOU provides that the State Government shall enter into a mutually acceptable Power Purchase Agreement.

पीपावव विद्युत परियोजना का प्रारम्भ किया जाना

1010 श्री अजीत जोगी :

चौधरी हरि सिंह : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पीपावव विद्युत परियोजना के निर्माण पर गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष कितनी-कितनी धनराशि खर्च हुई है ।

(ख) क्या सरकार को ताप्ती गैस पाइप लाइन के माध्यम से इस संयंत्र को गैस की सप्लाई करने के लिए विभिन्न संगठनों, संसद सदस्यों और गुजरात सरकार से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं ;

(ग) यदि हां, तो 30 नवम्बर, 1992 की स्थिति के अनुसार प्राप्त अभ्यावेदनों का ब्यौरा, क्या है,

(घ) इन पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है; और

(ङ) इस संयंत्र को कब तक चालू कर दिया जाएगा ?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. वी. रंगैया नायडू) : (क) से (ङ) पीपावव संयुक्त साइकल गैस टर्बाइन परियोजना (615 मे. वा.) पर निर्माण कार्य गैस लिंकेज सुनिश्चित किए जाने तथा परियोजना को सरकार द्वारा स्वीकृत किए जाने के पश्चात् ही आरम्भ हो सकेंगे । प्रस्तावित पीपावव परियोजना के लिए ताप्ती गैस क्षेत्रों में गैस का आवंटन किए जाने हेतु राज्य सरकार तथा अन्य सूत्रों से कई प्रतिवेदन प्राप्त हुए हैं जिनमें प्रधान मंत्री तथा पैट्रोलियम मंत्री को भेजे गए ज्ञापन भी शामिल हैं । तथापि, गैस का उत्पादन किए जाने हेतु ताप्ती क्षेत्रों का विकास करने के लिए निवेश सम्बन्धी योजनाओं को अभी अंतिम रूप नहीं दिया गया है ।

Failure of Power Corporations to Raise Funds

1011. SHRI MURLIDHAR CHANDRAKANT BHANDARE :
SHRI RAJNI RANJAN SAHU :

Will the Minister of POWER be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Power Corporation have failed to raise the funds through the bonds flouted by them this year.

(b) if so, the amount of funds proposed to be raised and the actual amount raised by each Corporation against different bond-schemes; and

(c) what are the reasons for the shortfall ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF POWER (SHRI P. V. RANGAYYA NAIDU) : (a) and (b) Yes, Sir. A statement indicating the allocation of bonds during 1992-93 to the Public Sector Undertakings under Ministry of Power and details of the amounts raised by them is attached. [*See* below]